(ग) इस पर कितना व्यय हुआ

अणु शक्ति विभाग में राज्य-मंत्री (श्री एच० एन० मुखर्जी स्वामी) : (क) तथा (ख). जी, अब तक नहीं। इस केन्द्र की स्थापना का काम जारी है तथा यह अगस्त, 1967 में काम करना शुरू कर देगा ।

(ग) इस केन्द्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि से प्राप्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से की जा रही है । इस निधि से प्रायोजना के लिए छः लाख पच्चीस हजार डालर की सहायता मिल रही है । चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रायोजना के सिविल कार्यों, अतिरिक्त उपकरणों आदि पर खर्च होने वाला सरकारी हिस्सा अनुमानतः सतानवे लाख पचास हजार रुपये होगा । गुजरात सरकार द्वारा प्रायोजना के लिए मुफ्त दी गई भूमि की अनुमानित कीमत 22 लाख रुपये आंकी गई है और यह उपरोक्त खर्च में शामिल नहीं है ।

Manufacture of Marine Diesel Engines

1473. **Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have approved the project for the manufacture of Marine Diesel Engines in India;

(b) if so, when; and

(c) the total amount of expenditure involved in the project?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir.

(b) 31st March, 1967.

(c) The estimated capital expenditure on the project is about Rs. 363 lakhs.

Anti-Indian Propaganda by China

1474. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Meetha Lal:
Shri Atam Das:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether China has stepped up anti-Indian propaganda and subversive activities in India; and

(b) if so, the steps which are being taken to counteract their activities?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) The Government are fully aware of the Chinese threats and all necessary steps are being taken to protect our national security.

इसराईल के साथ सांस्कृतिक अथवा व्यापार करार

1475. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अब तक इसराईल के साथ कोई सांस्कृतिक अथवा व्यापार करार किया है ;

(ख) क्या इसराईल ने राजस्थान के मरुस्थल की हरीभरी भूमि में परिवर्तन करने के लिये एक पाइप-लाइन सिंचाई योजना बनाने की पेशकश की है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रस्ताव किन कारणों से स्वीकार नहीं किया ; और

(घ) इस समय इसराईल में भारतीय हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० का० पाण्डया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). 1963 में इसराईल की सरकार ने निर्धारित तरीके के विपरीत राजस्थान सरकार को सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में सहायता देने की सीधे ही पेशकश की। चूंकि निर्धारित तरीके का पालन नहीं किया गया था, इसलिए इस प्रस्ताव पर आगे कुछ नहीं किया गया।

(घ) इस समय भारत के कौंसली हितों की देखभाल तेल-अवीव में ब्रिटेन का राजदूतावास कर रहा है।

टेलीविजन उपकरण में आत्म निर्भरता

1476. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कब तक टेलीविजन प्रसारण तथा टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये आवश्यक सभी उपकरणों के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगा ताकि उनके आयात पर विदेशी मुद्रा न खर्च करनी पड़े ; और

(ख) समूचे देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग की स्थापना पर कितनी भारतीय मुद्रा तथा कितनी विदेशी मुद्रा के खर्च होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख). टेलीविजन प्रसारण उपस्कर

टेलीविजन प्रसारण उपस्कर केवल दिल्ली में लगाया गया है जिसमें अभी तक विदेशी उपकरणों का इस्तेमाल होता है। टेलीविजन प्रसारण उपस्कर और स्टूडियो उपस्करों के देश में ही बनाने के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

इलैक्ट्रोनिक रिसीविंग सेट

सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पिलानी द्वारा तैयार किए गए देशी तकनीकी विधि का उपयोग करते हुए दो कम्पनियों को प्रति वर्ष दस-दस हजार टेलीविजन रिसीवर बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इन दोनों कम्पनियों का इस पर पूंजीगत व्यय 50 लाख रुपये के लगभग पड़ेगा जिसमें 7० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा होगी।

प्रारम्भ में प्रत्येक टेलीविजन रिसीवर पर लगभग 235 रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। पांचवें वर्ष में, जब कि बाहर से मंगाये जाने वाले उपकरणों का धीरे धीरे देशी उत्पादन आरम्भ होने लगेगा, प्रति रिसीवर पर 40 रुपए की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी।

परन्तीवर में बाहर से मंगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण टेलीविजन पिक्चर ट्यूब है जिसे देश में ही बनाए जाने की सम्भावना है और इससे प्रत्येक टेलीविजन रिसीवर में आयात किए जाने वाले उपकरणों की कीमत कम होने में मुख्य रूप से सहायता मिलेगी।

पनडुब्बियों का निर्माण

1477. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पनडुब्बियों के निर्माण करने की एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अपनी परमाणु नीति के संदर्भ में सरकार ने यह निर्णय भी किया है कि रक्षा-कार्यों के लिए परमाणु पनडुब्बियों का भी निर्माण नहीं किया जायेगा ; और